

RKL/SX/2022-23/16 May 31, 2022

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai – 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai – 400 051.

Scrip Code: 532497

Scrip Code: RADICO

Sub: Submission of copies of published Audited Financial Results

Dear Sir/ Madam.

In continuation of our letter dated May 30, 2022, we enclose copies of the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2022, as published today in "Business Standard" (English) and "Hindustan", Moradabad edition (Hindi).

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Radico Khaitan Limited

(Dinesh Kumar Gupta) Vice President – Legal & Company Secretary

Email Id: Investor@radico.co.in

Encl.: As above

Radico Khaitan Limited

Plot No. J-1, Block B-1, Mohan Co-op. Industrial Area Mathura Road, New Delhi-110044

Ph: (91-11) 4097 5444/555 Fax: (91-11) 4167 8841-42 Registered Office: Bareilly Road, Rampur-244901 (U.P.) Phones: 0595-2350601/2, 2351703 Fax: 0595-2350009 e-mail: info@radico.co.in, website: www.radicokhaitan.com

CIN No. L26941UP1983PLC027278

जीडीपीवृद्धि दर 4.5% से कम रहने की आशंका क्रिप्टोकरंसी पर परामर्श पत्र जल्द

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के संकेतों के बीच सबकी नजरें पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों पर है। सरकार की ओर से मंगलवार को जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि

चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसदी से नीचे रह सकती है जो तीसरी तिमाही के 5.4 फीसदी से कम है। भारतीय स्टेट

(एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है। कि देश की जीडीपी दर चौथी तिमाही में 2.7 फीसदी रह सकती है। यह अन्य सभी अनुमानों में सबसे कम है। वहीं रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 3.5 फीसदी रह सकती है। इक्रा ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि अंतरराष्टीय स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में तेजी और पिछले साल का उच्च आधार दर है। कमोडिटी के दाम बढ़ने से कंपनियों ने विस्तार की रफ्तार घटाई है जिसका असर वृद्धि दर पर पड़ सकता है।

बाजार के बिगड़े हुए मूड से अटके 1.6 खरब के आईपीओ

नर्ड दिल्ली। शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव की वजह से करीब 1.6 लाख करोड़ (खरब) रुपये निर्गम (आईपीओ) अटके पड़े हैं। कंपनियां और निवेशक बाजार के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से करीब 89 हजार करोड़ रुपये के आईपीओ को मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन बाजार के मौजूदा हालात को देखते हुए कंपनियां साहस नहीं जुटा पा रही हैं। हालांकि, कुछ आईपीओ को सेबी की सख्ती की वजह से भी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी कई मानकों पर कंपनियों के मूल्यांकन को परख रहा है।

बाजार सुधरने की आस : विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनियाभर के निवेशक सहमे हुए हैं और बेहद सधा हुआ कदम उँठा रहे हैं।

શેયર बાजારોં મેં તીસરે दिन भी लगातार तेजी

शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और दोनों मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी करीब दो प्रतिशत उछलकर बंद हुए। वैश्विक बाजारों में मजबत रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस में तेजी के साथ बाजार में मजबूती आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,041.08 अंक यानी 1.90 प्रतिशत चढकर ५५.९२५ .७४ अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 1,197 .99 अंक तक चढ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ३०८ .९५ अंक यानी १ .८९ प्रतिशत के लाभ के साथ 16,661.40 अंक पर mint

पिछले साल दो हजार के जाली नोट 54 फीसदी बढ़े

बंद हुआ।

मंबर्ड. एजेंसी। बीते वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग प्रणाली में मिले जाली 500 रुपये के नोटों की संख्या इससे पिछले वित्त वर्ष (2020-21) की तुलना में दोगुना से भी अधिक होकर 79,669 पर पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में 2,000 रुपये मूल्य के 13,604 जाली नोटों का पता चला। 2020-21 से 54.6 प्रतिशत अधिक हैं। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। बीते वित्त वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में मिले विविध मूल्यों की कुल जाली भारतीय करेंसी नोट की संख्या बढ़कर 2,30,971 हो गई जो 2020-21 में 2,08,625 थी।

एलआईसी का लाभ १७ फीसदी घटा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सोमवार को बताया कि मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष 2021–22 की चौथी तिमाही में उसका समेकित लाभ २,४०९ .३९ करोड़ रुपये रहा जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि से 17 .41 प्रतिशत कॅम है। एलआईसी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक दस रुपये के अंकित मूल्य के शेयर पर 1.50 रुपये की दर से लाभांश की सिफारिश की है।

महंगाई से जंग में विकास की बलि नहीं देंगे: दास

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले दिनों कहा था कि महंगाई रिजर्व बैंक के लिए प्रमुख चुनौती जरूर है लेकिन इसपर अंकुश के लिए विकास की बिल नहीं चढ़ने देंगे। दास ने कहा था कि एक संतुलित नजरिया अपनाया जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक छह से आठ जून के बीच होनी है। उल्लेखनीय है कि जीडीपी दर में तेजी आने पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।



आयुर्वेदिक एव यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित) पदो की दिनांक 29 मई 2022 को आयोजित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा की उत्तर कंजिका सम्बन्धी विज्ञपि

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 29 मई, 2022 समय प्रातः 11.00 से अपरान्ह 01.00 बजे तक आयोजित आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित) पदों की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की चारों उत्तर कुजियों (A,B,C&D) को बोड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है, जो दिनांक 30 मई 2022 सांय 06:00 बजे से दिनांक 05 जुन 2022 सांय 05.00 बजे (अंतिम तिथि तथा समय) तक बोर्ड की उक्त आधिकारिक वेबसाइव पर उपलब्ध रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र की चारों सीरीज के किसी उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारुप र ही आपत्ति अंकित कर बोर्ड की ई—मेल ukmssbexam@gmail.com पर साक्ष्य सहित दिनांक 05 जून 2022 (सांय 05.00 बजे) तक प्रेषित कर सकते है। बिना साक्ष्य के प्राप्त ई-मेल पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। उक्त ई-मेल के अत्तिरिक्त अन्य किसी ई–मेल पर, डाक अथवा किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति तथा अंतिम तिथि एर समय के उपरान्त प्रेषित आपत्ति को किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

गरिमा रौंकली, सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

कहा है कि मानसून रिजर्व बैंक और सरकार

सेठ ने कहा कि क्रिप्टोकरंसी के मुद्दे पर घरेलू एवं अन्य भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा की गई है और उसी के आधार पर परामर्श पत्र तैयार किया गया है।

टाटा ने फोर्ड के संयंत्र के लिए करार किया

नर्ड दिल्ली। टाटा मोटर्स ने सोमवार को कहा कि उसकी अनषंगी टाटा पैसेंजर इलेक्टिक लिमिटेड मोबिलिटी (टीपीईएमएल) ने फोर्ड इंडिया (एफआईपीएल) की साणंद वाहन विनिर्माण इकाई के अधिग्रहण के लिए गुजरात सरकार के साथ करार किया है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड दूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड 🎏

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः 11वां तल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

			(राश रु. लाख म)							
	क्र.	विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त	वर्ष				
	सं.	1441-1	31.03.2022 31.12.2021 3		31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021			
			(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)			
	1	प्रचालनों से राजस्व	69,096.12	54,021.04	33,878.67	1,87,947.84	77,665.77			
	2	अन्य आय	2,583.29	1,630.08	1,946.45	7,282.55	8,498.38			
	3	कुल राजस्व	71,679.41	55,651.12	35,825.12	1,95,230.39	86,164.15			
	4	कर एवं अपवादात्मक मदों से पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	28,720.82	28,154.36	14,207.77	89,351.74	21,811.56			
	5	कर पूर्व एवं अपवादात्मक मदों के बाद अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	28,320.37	28,154.36	13,920.02	88,951.29	25,751.37			
	6	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	21,378.25	20,880.94	10,378.51	66,368.91	18,702.64			
	7	कुल व्यापक आय (लाभ ∕ (हानि) (कर—पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	21,666.20	20,936.08	10,669.10	66,806.91	19,015.32			
	8	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 2/- प्रत्येक)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			
	9	अन्य इक्विटी				1,72,388.05	1,29,581.14			
	10	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)*			·					
		मूल (₹)	2.67	2.61	1.30	8.30	2.34			
		तनुकृत (₹)	2.67	2.61	1.30	8.30	2.34			

*तिमाही के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं है। ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किये गये शेयरों की संख्या 8000 लाख है। (नीचे टिप्पणी सं. 11 देखें)

उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

- कम्पनी के वित्तीय परिणाम, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, समय–समय पर यथासंशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एएस) के अनरूप तैयार किये गये हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए आंकडें पूर्ण वर्तमान वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकडों और वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष की तिथि के आंकड़ों के बीच संतुलित आंकड़ें हैं।
- विश्व एवं भारत में कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के कारण आर्थिक कार्यकलापों में बड़ी बाधा आई और इनमें मंदी
- कम्पनी ने रेलवे बोर्ड से तीन निजी ट्रेनों की गैर-परिचालन अवधि के लिए 31 मार्च, 2021 तक रु. 2,793 लाख के निर्धारित शुल्क (निश्चित ढुलाई और अभिरक्षा शुल्क) को, इसे एक अप्रत्याशित स्थिति मानते हुए, माफ करने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और प्रतिबंध कम्पनी के नियंत्रण से बाहर थे। मामला लंबित है। तथापि, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन प्रभारों के लिए पर्याप्त
- 22 मार्च, 2020 से पहले दिए गए कैटरिंग अनुबंधों को महामारी के कारण शून्य अवधि के रूप में माना गया है और तदनुसार वर्ष 2020–21 के दौरान एवं 26.11.2021 तक की अवधि के लिए कोई आय के साथ ही रेलवे का अंश अर्जित नहीं हुआ है 27.11.2021 से चरणबद्ध तरीके से पके हुए खाने के साथ कैटरिंग सेवाएं पूनः प्रारंभ कर दी गई हैं और आय एवं देय रेलवे शेयर तदनसार उपार्जित किया गया है। तथापि. 18.11.2019 से 23.03.2020 तक और 27.11.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया और रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सीसी 60 ऑफ 2019 के अनुसार कैटरिंग टैरिफ में वृद्धि के कारण इसे मान्यता दी गई है, चूंकि महामारी के कारण कम्पनी द्वारा बिक्री का
- . रेलनीर के पीपीपी प्लांटों के संबंध में प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि बिक्री के न्यूनतम सूनिश्चित स्तर की प्रतिबद्धता के बदले क्षतिपूर्ति ऑपरेटरों को भुगतान नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ डीसीओ ने कम्पनी के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया है और वित्तीय प्रभावों की गणना (लाइसेंस शुल्क छूट के निवल) 31 मार्च, 2022 तक रु. 194.44 लाख (पिछले वर्ष रु. 243.17 लाख) है जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लेखा बहियों में शामिल किया गया है।
- क्रिस से मांग का आधार / सूचना न मिलने के कारण कम्पनी द्वारा अनुमानित अनुसार 31 मार्च, 2021 एवं 31 मार्च, 2022 का समाप्त वर्ष के लिए तेजस टेनों के लिए कम्पनी द्वारा भारतीय रेल के पीआरएस का उपयोग करने के लिए प्रभार हेत वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु. 184.98 लाख का प्रावधान किया गया है।
- (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रू. 400.45 लाख की असाधारण व्ययों में (i) निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) के संबंध में पिछले वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान के व्युत्क्रम के रूप में रु. 2248.54 लाख (ii) 31.03.2021 तक रेलनीर प्लांट के लाभ में 15 प्रतिशत रेलवे शेयर के कारण व्यय के रूप में रु. 2713.32 लाख जैसा कि रेलवे कम्पनी के विवाद से सहमत नही है अर्थात् रेलनीर कैटरिंग सेगमेंट का भाग है जो कि घाटे में है; और (iii) विभिन्न अन्य व्ययों के संबंध में पिछले वर्षों के लिए रिटन बैंक अतिरिक्त प्रावधान के रूप में रु. 64.33 लाख शामिल है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रु. 3939.81 लाख की असाधारण आय में (i) निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) के संबंध में पिछले वर्षों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की व्युत्क्रम के रूप में रु. 2576.18 लाख (ii) जुलाई, 2015 से चालू किये गये यात्री फीडबैक के भुगतान के लिए रेलवे को किये गर्य दावे के रूप में रु. 1005.27 लाख जहां रेलवे इस दावे से सहमत नहीं है और (iii) विभिन्न अन्य व्ययों के संबंध में पिछले वर्षों के लिए रिटन बैक अतिरिक्त प्रावधान के रूप में रु. 358.36 लाख शामिल है

- 10.अब तक रेलवे टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए कम्पनी के पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से प्राप्त एकीकरण प्रभार (अ-प्रतिदेय एक बार) की गणना वित्त वर्ष 2020-21 तक एक से तीन वर्षों की प्रारंभिक अनुबंध अवधि के भीतर राजस्व के रूप में की गई है। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' पर भारतीय लेखाकरण मानक 115 ("इंड एएस") की आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी ने अनुमानित अनुबंध अवधि (पिछले अनुभव के आधार पर अनुमानित 20 वर्ष) के भीतर एकीकरण प्रभार से आय दर्ज की है, चुंकि कम्पनी यह अनुमान करती है कि एकीकरण के लिए ये अनुबंध और वार्षिक रखरखाव प्रभार सामान्यतः कम्पनी द्वारा नवीनीकृत किये जाते हैं और इसलिए इन्हें विशिष्ट अनुबंध के रूप में नहीं माना गया है। लेखाकरण पद्धति / नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में रु. 342.27 लाख (आस्थगित कर रु. 115.13 लाख का निवल) (पिछले वर्ष रु. 56.04 लाख (आस्थिगित कर रु. 18.85 लाख का निवल) की कमी हुई है और 31 मार्च, 2020 को प्रतिधारित आय में
- शामिल अन्य इक्विटी में रु. 1325.70 लाख (आस्थगित कर रु. 445.91 लाख का निवल) की कमी हुई है। 1. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने निदेशक मंडल द्वारा की गई सिफारिश और कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसार 29 अक्टूबर 2021 से अंकित मूल्य रु. 10 / – प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त अपने 1600 लाख इक्विटी शेयरों को अंकित मूल्य रु. 2 / – प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त 8000 लाख इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया है। लागू इंड एएस के प्रावधानों और पिछली अवधियों / वर्ष के तुलनात्मक ईपीएस के आंकड़े को बनाने के लिए ऐसे उप–विभाजन के बाद इक्विटी शेयरों की नई संख्या पर विचार करने के पश्चात सभी अविधयों के लिए प्रति शेयर अर्जन की गणना की गई है/उसे पुनः वर्णित
- 12. कम्पनी के निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन रु. 1.50 प्रति शेयर (अंकित मूल्य रु. 2/- प्रति शेयर) अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है और इसके अलावा, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए
- रु. 2/- प्रति शेयर (अंकित मूल्य रु. 2/- प्रति शेयर) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। 13.जहां कहीं आवश्यक / अपेक्षित हुआ, पिछली अवधियों के आंकड़ों को पुनः समूहित / पुनः वर्गीकृत / पुनः वर्णित

कृते निदेशक मंडल की ओर से

रथान: नर्द टिल्ली दिनांक: 30 मई, 2022

रजनी हसीजा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन≔ 08083674

ह0/- (इंजी. वी.पी. शर्मा)

ह0/- वी.पी. यादव

डिप्टी एस.ई. (सी) डीआर-VIII

ईई(सी) डीआर- XII

दिल्ली जल बोर्ड : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार कार्यालय अति. सीई (डीआर) प्रोजेक्ट-III, मार्फत अधिशासी अभियंता(सी)(डीआर)-XII एमयू ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 फोन: 011-27342465, ईमेल: executiveengineercdr12@gmail.com नि.आ.सू. सं. 04/ईई(सी) डीआर XII/2022-23 कार्य निविदा का नाम निविदा

ई-प्रापण हल के जरिए आरटीजीएस एवं डाउनलोड करने की अंतिम तिथि/समय वाटर साइक्लिंग टेक्नोलॉजी के साथ वैक्यूम सुपर सकर्स और जेटिंग कम सक्शन मशीनों के साथ निलोठी एसटीपी के कमाण्ड एरिया में 900 मि.मी. डाय रु.1500/ रु. 8,70,100/ 08.06.2022 अप. 03.00 बजे तक और अधिक आकार की पंजाबी बाग टंक सीवर की गांद निकालना। निविदा आईडीः 2022_**DJB**_223233_1

निविदा को वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

ननसंपर्क अधिकारी (जल) द्वारा जारी कोरोना रोकें : मास्क पहनें, दो गज की दूरी का पालन करें और हाथों को स्वच्छ रखें वेज्ञापन सं. ज.सं.वि. 151/2022-23

उप अधीक्षण अभियंता (सी) डीआर.-VIII द्वारा कार्यालय एसीई (डीआर.) प्रोजेक्ट-III



निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय विधानसभा क्षेत्र गोकलपुर एसी-68 की विभिन 2022 **DJB** 16.06.2022 2,63,92,700/ 5.27.900/ हालोनियों में चैम्बर का निर्माण और हाउस विधानसभा क्षेत्र करावल नगर एसी-70 की 2022 DJB 3.47.27.322/-6.94.550/ 16.06.2022 वेभिन्न कालोनियों में चैम्बर का निर्माण और अप. 3.00 बजे तक 223026 2 हाउस सर्विस सीवर कनेक्शन प्रदान करना। दि. 25.05.2022

दो गज की दूरी का पालन करें''

इस संबंध में आगामी विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देख सकते हैं। ज.सं.अधि. (जल) द्वारा जारी

विज्ञा.सं. ज.सं.वि. 152/2022-23

डा. ललित खेतान चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डीआईएन सं. 00238222

नर्ड दिल्ली। आर्थिक मामलों के मानसून महंगाई से दिलाएगा राहत: रिजर्व

सचिव अजय सेठ ने सोमवार को कहा कि क्रिप्टोकरंसी पर एक परामर्श पत्र को अंतिम रूप दिया जा चुका है और जल्द ही इसे पेश किया जाएगा।

र्ड-निविदा सचना

बैंक के पर्व डिप्टी गवर्नर आर.एस. गांधी ने

को महंगाई की चुनौती से निपटने में मदद करेगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/मुख्यालय/मुरादाबाद द्वारा ई टेन्डर निम्न टेन्डर संख्या के अर्न्तगत आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपाजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टेन्डर से संबंधित अन्य जानकारी वैबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

	टेन्डर संख्या दिनांक	36-DRM-MB-22-23 dt.28.05.2022	37-DRM-MB-22-23 dt.28.05.2022		
0 हे ति ई त	कार्य का नाम	Reconditioning of Tounge Rail, SEJ and CMS Crossings in the section of ADEN/HQ/MB and ADEN/CH.	Replacement of Bed Block at Bridge No 21 & 18 (CH- BE Section) under ADEN/CH (Having bridge in ORN 03). Chargeable to Est No 72/2022.		
2 ਟ ਵ	टेन्डर क्लोसिंग दिनांक/ समय	21/06/2022 16:00	21/06/2022 16:00		
में	अनुमानित लागत	3644532.14	13378721.84		
य	धरोहर राशि	72900.00	216900.00		
य	टेन्डर फार्म की लागत	0.00	0.00		
य वं	बिडिंग स्टार्ट तिथि	07/06/2022	07/06/2022		
٦	कार्य पूर्ण करने की अवधि	6 Months	6 Months		
	ਜਂ.:- 75-W/2/3/WA/Publica	ation दिनांक: 28.05.2022	1298/2022		



31 मई 2022 जनपद- मुरादाबाद



- गुटखा, खैनी, सिगरेट, हुक्का एवं अन्य तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन जानलेवा हो सकता है।
- तंबाकू पदार्थों के सेवन से मुंह, फेफड़े का कैंसर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एवं कोरोना वायरस के संक्रमण जैसी गम्भीर एवं जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

सार्वजनिक स्थानों पर थुकना दण्डनीय अपराध है। तंबाकू पदार्थी का सेवन न करें। आज ही छोड़ें ! अभी छोड़ें !

नशे को अलविदा करने का यही है सही वक्त, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं और हमेशा के लिये छुटकारा पाएं।

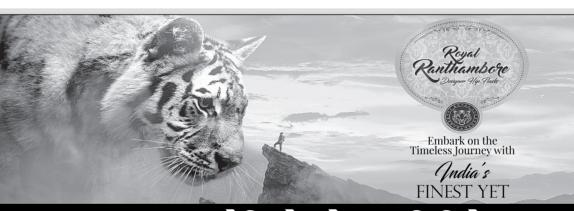


तंबाकू युक्त पदार्थों के सेवन से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आई.ई.सी. सेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, मुरादाबाद

डॉ. एम.सी. गर्ग मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद

डॉ. दीपक वर्मा नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद

शैलेन्द्र कुमार सिंह (आई.ए.एस.) निर्लाधिकारी मुरादाबाद





डिको खेतान

पंजीकृत कार्यालय : बरेली रोड, रामपुर-244 901 (उ.प्र.) फोन 0595-2350601/2, 2351703 फैक्स 0595-2350009 ई-मेल: investor@radico.co.in वेबसाईट: www.radicokhaitan.com

सीआईएन : L26941UP1983PLC027278

(सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 47 (1) (बी))

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही व वर्ष (स्टैंडअलोन व समेकित) का (आंकडे ₹ लाखों में) परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (ईपीएस के सिवाय) स्टैं द्वयलो न **ய**ப் கெ எ

			स्टङ्गलान				समाकत					
_	क्र. सं.	. 1 + +	तिमाही समाप्त 31.03.2022 (परीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.12.2021 (अपरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.2022 (परीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2022 (परीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2021 (परीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.2022 (परीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.12.2021 (अपरीक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.2022 (परीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2022 (परीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2021 (परीक्षित)
I	1.	परिचालनों से कुल आय	322642.93	329894.61	295833.57	1248152.96	1052411.43	322658.32	329885.16	295222.27	1247792.97	1051800.13
I	2.	शुद्ध लाभ (कर एवं (असाधारण मदों से पूर्व)	6294.04	10064.13	9443.66	33525.08	35310.16	6673.91	10306.33	9442.01	34631.52	35969.60
	3.	कर पूर्व शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	6294.04	10064.13	9443.66	33525.08	35310.16	6673.91	10306.33	9442.01	34631.52	35969.60
	4.	कर के बाद शुद्ध लाभ (असाधारण मदों के बाद)	4636.06	7671.23	7354.97	25216.31	27056.36	5015.93	7913.43	7353.32	26322.75	27715.79
	5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	4751.14	7648.78	7397.82	25249.07	26970.12	5130.41	7891.15	7399.12	26355.41	27630.20
	6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रुपये 2/- प्रति)	2673.48	2673.48	2671.37	2673.48	2671.37	2673.48	2673.48	2671.37	2673.48	2671.37
	7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त) लेखा वर्ष 31.03.2022 के अंकेक्षित तुलन—पत्र के अनुसार	1	-	I	196007.09	173719.31	1	1	1	197111.29	176620.22
	8.	आय प्रति शेयर कर के बाद शुद्ध लाभ पर पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर रुपये 2/- प्रति)										
		(क) मूल :	3.47	5.74	5.51	18.87	20.26	3.75	5.92	5.51	19.70	20.75
		(ख) तरल ः	3.47	5.74	5.51	18.87	20.25	3.75	5.92	5.50	19.70	20.74

टिप्पणी : (1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष समाप्त के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टेंडअलोन एवं समेकित) को जिसकी समीक्षा अंकेक्षण समिति द्वारा की गई है और इसे निदेशक मंडल ने सोमवार दिनांक 30 मई, 2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय परिणामों पर असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है। (2) उपरोक्त सारांश तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्वेंजों में दायर किया गया है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् www.radicokhaitan.com, www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। (3) कम्पनी के निदेशक मंडल ने अपनी आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए 150% के लाभांश की सिफारिश की है यानि 2.00 रू. के अंकित मूल्य के 3.00 रू. प्रति इक्विटी शेयर जो कि 4,010.21 लाख रूपये की राशि है। (४) यह कथन कपनियां (भारतीय लेखा मानकों) नियम, २०१५ (आईएनडी–एएस) के अनुपालन में कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३३ और अन्य मान्यताप्राप्त लेखा मानकों और नीतियों के अनुसार लागू सीमा के अनुसार तैयार की गई है। कृते रेडिको खेतान लिमिटेड

नई दिल्ली 30.05.2022

A power crisis on an old track

The Railways' decision to stick with steel wagons may have contributed to the shortage of rakes to haul coal to generating plants

SUBHOMOY BHATTACHARJEE New Delhi, 30 May

he Indian Railways has had a solution to the current crisis of wagon shortage for the past two decades, but never implemented it. The idea was to consider the use of aluminium progressively to build wagons, adding to its steel and stainless steel made fleet. This transition would have cut costs and substantially added to freight haulage capacity without adding more engines, crew or fuel costs. The initial higher investment would have been repaid by higher capacity.

This year, the Railways is gasping to balance demands industry for faster coal supplies with the demands of other industries. It has to keep rakes ready to meet the rising demand for just about every other bulk commodity, from cement and steel to sand and food grains. The organisation has a stock of 304.582 wagons as of March 2022. This is clearly a woefully inadequate number, which is why Railway Minister Ashwini Vaishnaw has rushed to announce plans to add 90,000 wagons in three years. These will be built with stainless steel. The first of contract to supply 24,177 of those wagons, at a cost of ₹7,838 crore to the Railways, according to the company's notice filed with the Bombay Stock Exchange

Sitharaman had, meanwhile, sition. In 2001, the governindicated plans to expand the use of aluminium in passenger coaches. In her Budget speech this February, the min-Bharat trains will be introduced. These, it is understood. shall be made mostly of lightweight aluminium. It is interesting that while the Indian had sent the Railways a pro-Railways is willing to switch posal to this effect.



from the thermal power to aluminium-based passenger coaches, it is not ready to ask private sector wagon suppliers to consider the same idea, even after debating it for almost two decades.

The Railways had warmed to the idea of aluminium wagons in 2003 and asked its research arm. Research Designs and Standards Organisation (RD&SO), to develop a techno-economic feasibility study. In its report, RD&SO noted, "Aluminium wagons besides being of a lower cost and having a lower tare weight [the weight of an empthose tenders is already out. ty vehicle], also have the Titagarh Wagons has won the advantage of suffering less corrosion in many circumstances. A typical rake with aluminium wagons instead of steel ones would carry almost 240 tonnes more goods.

Naturally, the aluminium Finance Minister Nirmala industry lobbied for this tranment had privatised Balco and production of aluminium had begun to expand both from it. as well as from state-owned ister said 400 more Vande Nalco. The mines ministry encouraged the Railways to make the switchover. Secretary, ministry of mines, AK Kundra told the media he

ON THE WAGON

Daily rake loadings: 1,302 Number of wagons:

305,150 Average number of wagons loaded per day: **65,752**

Average load per wagon: **61.84** tonnes

Average load per wagon excluding container services):

66.84 tonnes Claimed carbon emissions saved (from freight

4,502,822 tonnes

The tare weight of a steel wagon is typically 21 tonnes. With a full load of 55 tonnes, the combined weight is 76 tonnes on the rail lines. An aluminium wagon is lighter. "Our present ratio (gross load to tare) is 2.5. With aluminium we can double this," said a railway ministry official. A recent paper in the global trade magazine FreightWaves noted, "With more tonnes per loaded railcar, fewer railcars and less

a given amount of freight." 'The initial cost is high and that prevented any further move even though alu-

fuel are required to transport

minium wagons last longer. are relatively easy to handle and there are examples of their use from railways across the world," said Sunil Chaturvedi, chairman and managing director of capital goods firm Gainwell Commosales and a former IAS officer with some experience of handling

the Railways. Predictably, the domestic iron and steel industry lobbied against the switch. The national steel policy of 2017 estimates the current total usage of steel in railways at 3 per cent of its total output and this is expected to grow. Matters were also helped by a Railways policy that insists that it retain all intellectual property rights on designs for its coaches, locomotives and wagons.

"Even now the Railways acquires the design of the wagons even though their production is largely with the private sector by paying them a royalty. If the companies make any subsequent improvements in design those too have to be shared with the Railways, which will offer the same to the competitors," said Mukesh Kumar Singh, former CMD of Ircon, a railway consultancy enterprise.

But the best of the new technology could only come from abroad. Those companies were willing to build the wagons here but would not share their technology. In their absence, the domestic designs by RD&SO did not offer a compelling cost advantage. The decision therefore stalled.

Other than the challenge of initial costs was the unstated fear that a switchover to the new rakes would make redundant the large infrastructure built to service the wagons. This included investments made by private sector companies, too, which in turn had spawned a large ancillary industry. It was not clear how and to what extent the foreign supplier companies would replicate such an environment. Messages to companies

(such as Titagarh Wagons) on the issue remained unanswered. Though no Railways official was willing to comment on the issue on the record, in debates within the ministry, they held up the risks of using aluminium in handling bulk cargo. A decade ago (September 2012), the Railway Board had flagged the risk of damages to even the steel-built railway wagons by the use of mechanised loading of bulk cargo without safeguards. Based on this, RD&SO was asked to "frame standard instructions to customers to regulate use of such mechanized loading/unloading equipment". Singh said those risks of damage to railway wagons would be far higher for aluminium-built wagons.

The basic challenge, as the FreightWaves article notes, is the comparison of costs. There will be a higher cost to make the switch, but compensating those would be savings from fewer journeys. The savings will be on fuel budgets, fewer employees and therefore making do with less investment for new wagons. Busier routes will have faster turnarounds. Fewer trips will also mean a positive environmental footprint for the Railways.

ON SENTIMENTS Sentiments sour



MAHESH VYAS

Something snapped in the week ended May 29, 2022. The Index of Consumer Sentiments (ICS) tanked by 9.4 per cent. This is an unusually sharp fall. Sentiments fell across urban and rural regions, but with varying intensity. The ICS fell by 5.9 per cent in urban regions and by a much steeper 11.4 per cent in rural regions. The 30-day moving average as of May 29 dropped to 67.91 (base 100 in September-December 2015). It was 68.09 just a day earlier.

The ICS had closed April 2022 at 67.2. As of May 29, it was still a per cent higher. The month of May could still end with the ICS higher than it was in April. If it does so, it would be the highest compared to any month since March 2020 — i.e. before the lockdowns. However, there are signs that the steady improvement in consumer sentiments seen so far during 2022 may be slowing, or even reversing.

The final ICS data for May will be available only on June 1. However, using the 30-day moving indices generated every day by CMIE, it is safe to assume that the index will be marginally higher than April. But the slender growth in May also implies a slowing down of the monthly growth rate of the ICS. During the previous four months, January through April, the ICS saw monthly growth rates between 3 per cent and 5 per cent.

Compared to other economic indicators, the recovery in the ICS from the lockdown-induced drop in April 2020 has been distinctly slower. Most economic indicators have recovered to their pre-lockdown levels. For example, real gross domestic product (GDP) and gross value added (GVA) in 2021-22 were

respectively, than in 2019-20: and the central government's total tax collection in 2021-22 was 25 per cent higher than in 2019-20. However, the ICS in April 2022 was a substantial 36 per cent lower than it was in February 2020. Apparently, ICS, which includes perceptions about current and future wellbeing of households, takes longer to recover from a severe economic shock.

There are three problems we see in the recent trajectory of

consumer sentiments in India. First, the relatively slow growth in consumer sentiments compared to other economic indicators mentioned above is slowing further in recent months. The ICS grew by 4 per cent in January and then the growth accelerated to 5 per cent in February. But in March, it slowed further to 3

The 30-DMA is a

less volatile

series than the

weekly series

and, therefore,

its accelerated

decline since

May 20 is

worrisome

per cent in April. And now in May, it is expected to slow down further probably to less than 1 per cent.

Second, the growth in consumer sentiments, which was slowing till recently, now

seems to be reversing. This is evident from the 30-day moving average (30-DMA) series of the ICS. The 30-DMA was rising steadily from a local trough in the series on April 22 when the index measured 64.01. By April 30, it had recovered to 67.02. Then, it marched up steadily to reach 70.04 on May 20. At this level it was already 4.2 per cent higher than the April level. But then began a fall, which looks like a reversal of the growth trajectory seen hitherto. By May 29, the 30-DMA ICS had fallen to 67.91, which was a mere 1 per cent higher than the April-end level.

The reversal is also evident in the weekly ICS data. The weekly index fell by over 11 per cent in the last two weeks of Mav.

Third, and probably the most worrisome part, is that the recent reversal is moving at a

about 2 and 3 per cent higher, distinctly faster pace than the pace of the recent rise. The fall in the 30-DMA between May 20 and May 29 is at the rate of 0.34 per cent per day. In comparison, the rise between April 30 and May 20 was at the rate of 0.22 per cent per day. The 30-DMA is a less volatile series than the weekly series and, therefore, its accelerated decline since May 20 is worrisome.

The trajectory of the ICS is changing because consumer expectations are turning adverse at a faster pace than consumer perceptions regarding their current well-being. This is evident in the data for each of the three trends of the ICS described above.

First, the slowdown is more pronounced in expectations. Between December 2021 and April 2022, while the ICS has grown by 3.9 per cent, the slowed down to 3.7 per cent. It index of consumer expectations (ICE) grew at a

slower rate of 2.9 per cent compared to the index of current economic conditions (ICC), which grew at 5.5 per cent. Second, the

reversal in consumer expectations is greater in the case expectations

(ICE) than current conditions (ICC). During the upswing, from April 30 through May 20, ICE grew by 4.8 per cent while ICC grew by a lower 4 per cent. But during the downfall from May 20 till May 29, the ICE fell by 2.9 per cent while ICC fell by only 2.5 per cent.

We do not know what could have caused the sentiments in general and expectations in particular to sour in recent times. Given that the fall was more striking in rural India, it is quite possible that the controls on wheat and sugar export could be responsible. We may conjecture that measures to control inflation hurt sentiments in rural India but the continued elevated inflation hurts urban India.

The writer is MD & CEO,



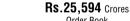
DILIP BUILDCON LIMITED

Registered Office: Plot No. 5 Inside Govind Narayan Singh Gate, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal-462016, Madhya Pradesh CIN: L45201MP2006PLC018689











11,237 Equipments



30,737

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Financial Results

(₹ in lakhs)

Rev	enue
2,51	,280

PAT 299

(₹ in lakhs)

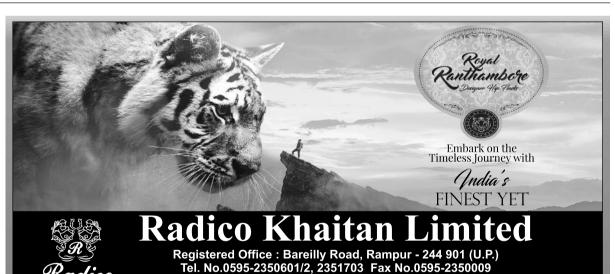
						(* 111 1411110)			
		Standalone							
Sr.	Particulars		Quarter ended		Year ended				
No	Farticulars	31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21			
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited			
1	Total Income from Operations (net)	251,279.93	220,738.38	292,993.75	904,017.59	923,799.64			
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	298.60	(9,666.44)	12,727.87	(8,597.36)	31,929.30			
3	Total Comprehensive income [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,516.53	(9,503.94)	13,296.00	(6,724.07)	32,488.62			
4	Equity share capital	14,621.50	14,621.50	13,676.98	14,621.50	13,676.98			
5	Earnings Per Share (before extraordinary items)(of Rs. 10/- each)(not annualised): (a) Basic (b) Diluted	0.20 0.20	(6.61) (6.61)	9.31 9.31	(5.91) (5.91)	23.35 23.35			
6	Earnings Per Share (after extraordinary items)(of Rs. 10/- each)(not annualised): (a) Basic (b) Diluted	0.20 0.20	(6.61) (6.61)	9.31 9.31	(5.91) (5.91)	23.35 23.35			

	(b) Diluted	0.20	(10.01)	9.31	(5.91)	23.33			
		Consolidated							
Sr.	Particulars	(Quarter ended	Year ended					
No		31-Mar-22	31-Dec-21	31-Mar-21	31-Mar-22	31-Mar-21			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income from Operations (net)	266,889.55	225,894.45	314,347.66	960,481.56	1,021,049.56			
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(4,109.53)	(9,689.20)	18,618.36	(54,967.59)	43,654.61			
3	Total Comprehensive income [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2,891.48)	(9,526.84)	19,186.50	(53,094.18)	44,213.94			
4	Equity share capital	14,621.50	14,621.50	13,676.98	14,621.50	13,676.98			
5	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)(not annualised): (a) Basic (b) Diluted	(2.81) (2.81)	(6.63) (6.63)	13.61 13.61	(37.77) (37.77)	31.92 31.92			
6	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)(not annualised): (a) Basic (b) Diluted	(2.81) (2.81)	(6.63) (6.63)	13.61 13.61	(37.77) (37.77)	31.92 31.92			

Notes:

- 1. The above standalone and consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 30 May
- 2. The above standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended standalone and consolidated financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website viz. www.dilipbuildcon.com.
- 4. Figures relating to previous periods have been regrouped / rearranged, wherever necessar

For and on behalf of the Board of Directors o



Email: investor@radico.co.in Web.: www.radicokhaitan.com CIN: L26941UP1983PLC027278

(Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulation 2015) Extract of Audited Financial Results (Standalone and Consolidated)

(₹ In lakhs)

for the quarter and Year ended March 31, 2022									(Exc	ept EPS)	
		Standalone					Consolidated				
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)
1.	Total income from Operations	322642.93	329894.61	295833.57	1248152.96	1052411.43	322658.32	329885.16	295222.27	1247792.97	1051800.13
2.	Net Profit (before Tax and Exceptional items)	6294.04	10064.13	9443.66	33525.08	35310.16	6673.91	10306.33	9442.01	34631.52	35969.60
3.	Net Profit before Tax (after Exceptional items)	6294.04	10064.13	9443.66	33525.08	35310.16	6673.91	10306.33	9442.01	34631.52	35969.60
4.	Net Profit after tax (after Exceptional items)	4636.06	7671.23	7354.97	25216.31	27056.36	5015.93	7913.43	7353.32	26322.75	27715.79
5.	Total Comprehensive Income for the period	4751.14	7648.78	7397.82	25249.07	26970.12	5130.41	7891.15	7399.12	26355.41	27630.20
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.2/- each)	2673.48	2673.48	2671.37	2673.48	2671.37	2673.48	2673.48	2671.37	2673.48	2671.37
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) in the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2022	-	-	-	196007.09	173719.31	-	-	-	197111.29	176620.22
8.	Earning per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs.2/-)										
l	(a) Basic	3.47	5.74	5.51	18.87	20.26	3.75	5.92	5.51	19.70	20.75
l	(b) Diluted	3.47	5.74	5.51	18.87	20.25	3.75	5.92	5.50	19.70	20.74

1) The audited financial results (standalone & consolidated) of the Company for the quarter and year ended March 31, 2022, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on Monday, May 30, 2022. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on financial results. 2) The above is an extract of detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.radicokhaitan.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. 3) The Board of Directors of the Company recommended a dividend of 150%, i.e. Rs 3.00 per equity share of face value of Rs 2.00 amounting to Rs. 4,010.21 lakhs for the approval of the shareholders at their ensuing Annual General Meeting. 4) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable

For and on behalf of the Board

Dr. Lalit Khaitan Chairman & Managing Director DIN No. 00238222







May 30, 2022

New Delhi



















